

[श्री राम बिनास पातशन]

कुल लागत 559.89 करोड़ रुपये को भी जो रद्द कर दिया। ज्ञातव्य है कि जिस विडना को कुल रू० 1951 में 153 करोड़ रुपये तथा टाटा को 116 करोड़ रुपये थी वह 1975-76 में बढ़ कर 1075 ए० 975 करोड़ क्रमशः हो गई।

सरकार द्वारा उपरोक्त लाइसेंस रद्द दिया जाना जनहित तथा सरकार की घोषित नीतियों के विन्मुख विपरीत है। अतः सरकार इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

(iv) REPORTED CANCELLATION OF PASSENGER TRAINS ON MANMAD-PURNA AND ADILABAD-PURNA ROUTES.

श्री केशवराव धोंडे (नांदेड़) :

सदर साहब, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर जनता के ससेले को यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य के अन्दर कोयले की कमी का एक कारण बता कर रेलवे विभाग ने मनमाड़-पूर्णा, आदिलाबाद-पूर्णा और पूर्णा-परली की पमेंजर रेल गाड़ियाँ सभी हाल ही में बन्द की हैं। यह गाड़ियाँ बन्द होने से महाराष्ट्र के खान तीर पर मगठनाड़ा प्रभाग की जनता पर इसका बहुत ही बुरा और गंभीर असर पडा है। हजारों गरीब यात्रियों को इस प्रमाण में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र और आंध्र के लोगों को भी इसकी वजह से बहुत मुश्किलता का सामना करना पड़ रहा है। यह रेलगाड़ियाँ बन्द होने से लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। यातायात का खर्चा भी बढ़ा है और लोग भी परेशान हैं। उनमें तीव्र असंतोष फैला हुआ है। यह गाड़ियाँ फौरन शुरू करना बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ और

इस बारे में वे स्टेटमेण्ट दें, इसके लिए मैं आपकी ओर से उनसे गुजारिश करना हूँ।

सदर साहब, मैंने कल ही मंत्री महोदय से मिल कर इस बारे में निवेदन किया है। आज वे यहाँ पर हाजिर थे उपास्यत हैं, मैं आपके द्वारा बिनती काहंगा कि मंत्री महोदय यहाँ पर स्टेटमेण्ट दें।

रेल मंत्री (प्र० मधु बण्डवते) : वह गाड़ी शुरू करने के आदेश हमने दे दिए हैं।

श्री केशव राव धोंडेग : मैं आपका आभारी हूँ।

(v) WORKERS' AGITATION IN HINDUSTAN AERONAUTICS, HYDERABAD

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Mr. Speaker, Sir, with your permission, under rule 377, I would like to bring to the notice of the Minister of Defence the present state of affairs in Hindustan Aeronautics, Hyderabad. There is, in this enterprise, an Avionic Design Bureau Air Force personnel who are posted in this Division are on deputation and are, therefore, not under the discipline and control of the management. For example, the management cannot conduct any inquiry into any complaints of harassment by any of these officers.

The present Head of the Department is said to be very arrogant in his behaviour towards the workmen and harasses them. Some time ago the workers went on an agitation in protest. About 100 of them were immediately issued notices of warning. Later the management withdrew the letters and agreed to review the position after three months.

But, within a few days of this, one of the workers was suddenly suspended